मिशन डाइवर्सिटी

2023

एच.एल. दुसाध

मिशन डाइवर्सिटी
2023

एच. एल. दुसाध

डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट
लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2025

प्रकाशक : **डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट**
डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467,
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191

© **डाइवर्सिटी ट्रस्ट**

मूल्य : ₹1300/-

रचना	:	**मिशन डाइवर्सिटी-2023**
लेखक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	कम्प्यूटेक सिस्टम
शब्दांकन एवं मुद्रण	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

समर्पण

नास्तिकता के प्रसार में जुटे
प्रख्यात चिंतन **उग्रनाथ श्रीवास्तव** सर को
जो दलित शासन की
उग्र हिमायत में अपनी कलम को सक्रिय
किए हुए हैं

अनुक्रम

लेखकीय *xi*

अध्याय-1 : 2003 का डायवर्सिटी चिन्तन

सावित्रीबाई फुले की जयंती पर संकल्प—शुरू हो शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की लड़ाई!—23, शुरू हो गई : नफरत की राजनीति—28, बेकाबू होती आर्थिक असमानता—32, विविधता केंद्रित सामाजिक परिवर्तन की अभूतपूर्व परियोजना—39, ऐसे नहीं बचेगा : हमारा लोकतंत्र—48, दुसाध के आत्मविश्वास में कुछ लोगों को कुंठा का प्रकटीकरण क्यों दिखता है!—52, बॉलीवुड को पुनर्जीवन दिया : पठान—59, अमृतकाल का बजट—65, डाइवर्सिटी एजेंडा लागू करवाने के लिए : क्यों नहीं आगे आ सकते बहुजनवादी दल!—69, माराडोना महानतम एथलीट एक्टिविस्ट भी रहे!—74, कांग्रेस ने खोला : सामाजिक न्याय का पिटारा—82, पुस्तक सप्लाई में लागू हो सामाजिक और लैंगिक विविधता—91, साहित्य अकादमी में नहीं है : डाइवर्सिटी!—96, इंटरव्यू बोर्ड में अनिवार्य हो सामाजिक और लैंगिक विविधता—101, शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन!—106, सबसे आसान काम है : भाजपा को शिकस्त देना!—111, बहुजन क्रांति स्तम्भ!—118, भाजपा की ताकत और कमजोरियां!—123, सामाजिक अन्याय के मुद्दे पर मोदी को घेरे विपक्ष!—127, कैसे लड़ें आंबेडकरवाद की रक्षा की लड़ाई!—140, मुस्लिम आरक्षण के खात्मे की ताक में : भाजपा—147, कांग्रेस के लिए : कर्णाटक का सन्देश!—154, भाजपा को परास्त करने के लिए : सामाजिक न्यायवादी विजन!—160, सामाजिक न्यायवादी विजन से ही हार सकती है : भाजपा—169, भाजपा की नफरती राजनीति का ठोस जवाब!—174, भाजपा की नफरती राजनीति

का योग्य जवाब!—180, सामाजिक विवेक की परीक्षा के सम्मुखीन खड़ाः अमेरिकी प्रभुवर्ग!—184, मोदी की छवि—189, विस्तार पाता अमेरिकी आरक्षण का दायरा!—194, मणिपुर का सबक—199, आजादी का अमृत महोत्सव के समापन पर क्या हो बहुजनों का संकल्प!—204, आज मनाया जायेगाः एक और डाइवर्सिटी डे!—210, लोकसभा चुनाव बहुजन बुद्धिजीवियों की अपील—214, नफरत की राजनीति के घातक नशे सेः कैसे बचे वंचित समाज!—224, उद्धव ठाकरे की चेतावनी—229, राममय बनता देश का माहौल!—233, बहुजनों को निराश करता : नारी शक्ति वंदन अधिनियम—237, मैंने क्यों नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दहन किया!—242, रागा की क्रांतिकारी घोषणा : जितनी आबादी—उतना हक—247, कांशीराम के भागीदारी दर्शन का बवंडर—252, तय हो गया कांग्रेस का चुनावी एजेंडा!—258, दलितों को सम्मान नहीं, अधिकार चाहिए!—262, बिहार में नौकरी की बहार—266, सत्ता परिवर्तन से ही बचेगा : संविधान—267, दलित-आदिवासियों के उत्थान में : कांग्रेस का योगदान—276, बाबासाहेब के मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी है : दलितों के नेतृत्व में एक नया स्वाधीनता संग्राम!—284, कांग्रेस ने बदली : देश की शक्ल—289

अध्याय-2 : 2023 में फेसबुक पर दुसाध

ताकि इक्कीसवीं सदी में फिर न अनुष्ठित हो कोई और कोरेगांव!—301, मेरे गुरू एसके विश्वास की किताब का ऐसा ही असर मुझ पर भी पड़ा!—302, मेवाती जी, आपके स्टैमिना को सौ 2 सलाम!—304, जनसंदेश के संपादक Subhash Rai सर का चिरऋणी रहेगाः दुसाध!—304, सवर्ण समाज में जन्में चैंपियन बहुजन हितैषी Sanjeev Chandan जी के कम्युनिस्ट ब्राह्मणों पर लिखे गए एक पोस्ट पर मेरी राय!—307, झारखंड में 25 करोड़ तक ठेकों में आरक्षण का सबब बना यह पोस्ट!—308, इसलिए कहता हूं आंबेडकरी आंदोलन जैसा व्यर्थ आंदोलन और कहीं नहीं हुआ!—309, काश! आंबेडकरवादी हिंदुओं अर्थात् सवर्णो की भांति वित्त वासना पालते!—310, जय हो मोदी कीः भारत निकल गया चीन से आगे!—312, पठान ने हिंदुओं अर्थात् सवर्णों की नामर्दी को एक बार फ़िर सतह ला दिया है!—312, दुसाध को इमोशनल बना देने वाला नम्बर 1 गाना!—313, पठान को बंपर हिट बनाने के लिए हीन मानसिकता ग्रस्त हिंदुओं को धन्यवाद!—315,

ब्राह्मण : यूनिवर्सल बोल्ट–316, महान मियांइन सानिया मिर्जा को बहुजनों की ओर से कोटि 2 भीम सलाम!–317, दिलीप तुम पॉपुलर नहीं, नोटेबल राइटर बनने की कोशिश करना : मेरे फिल्मों वाले गुरु एम एस सोढ़ी!–318, मेरी बबूनीः जिसने व्यक्ति के रूप में दुसाध को गर्वित होने का सबसे बड़ा अवसर मुहैया कराया!–319, क्या हमने गुरु रैदास के बेगमपुरा ड्रीम को जमीन पर उतारने की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाया?–320, जब माला सिन्हा के रूप में पहली बार किसी फिल्म एक्ट्रेस को करीब से देखा!–321, अर्थ, राज, ज्ञान और धर्म सत्ता के सर्वोच्च पद पर किसी हिंदू, खासकर उच्च वर्ण हिंदू को कभी काबिज नहीं होने देना चाहिए!–323, आर अश्विन बनाम ग्रेट शेन वार्न!–324, मुसलमान सेलिब्रेटीज की हिन्दू पत्नियां–325, हिंदुत्व के अर्थशास्त्र की रक्षा से जुड़ा है : वेलेंटाइन डे का विरोध! –326, वर्ल्ड बुक फेयर में दुसाध–330, सापेक्षिक वंचना का लाभ उठाने में व्यर्थ : बहुजन नेता–331, वामपंथ के अंत पर मोहर–332, मत भूलें, कांग्रेस सोनिया एरा में सांस ले रही है–333, साहित्य संस्थानों में जेंडर डाइवर्सिटी!–334, मोदी इसलिए बने ताकतवर–335, भाजपा को कांग्रेस जैसा बताने वाले क्या वर्ग शत्रु और वर्ग मित्र में फर्क समझते हैं!–336, आर्थिक रूप से समर्थ परिवारों के लोग ही सामाजिक बदलाव की लम्बी लड़ाई लड़ पाते हैं–337, बिना शक्ति के स्रोतों में विविधिता लागू करवाने की लड़ाई लड़ेः सामाजिक न्याय सपना ही बना रहेगा!–339, दुसाधः कलम का सबसे बड़ा निःशुल्क मजदूर!–341, एक ब्रह्मण लौंडे के आंबेडकर विरोधी करतूत पर मेरा कमेंट!–342, क्योंकि सवर्णों में वर्गीय चेतना है इसलिए वे आंबेडकर जयंती पर बधाई सन्देश नहीं देते!–343, राहुल गांधी ने निर्धारित तिथि पर खाली कर दिया सरकारी आवास!–346, पुस्तक दिवस की भूरि 2 बधाई!–349, मानव सृष्टि मेंः इवोल्यूशन बनाम डिवाइन थ्योरी!–350, यशस्वी जायसवालः वर्तमान पीढ़ी का सबसे गिफ्टेड स्ट्रोक प्लेयर?–351, भाजपा को हराने जैसा आसान पॉलिटिकल टास्क और नहीं–352, बोधिसत्व राजेन्द्र साहब ने फिर बनाया दुसाध को आभारी!–353, नागनाथ और सांपनाथ की थ्योरी साहब कांशीराम के राजनीतिक दूरदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करती है!–353, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मेनिफेस्टो में ये रहीं खास बातें!–355, नफरती गैंग की काट का फार्मूला–359, सोनिया और राहुल गांधी जैसे समग्र वर्ग की चेतना से समृद्ध नेता शायद ही स्वाधीन भारत की हिस्ट्री में कोई हुआ!–360, फेसबुक पर भक्तों का

बुरी तरह नियंत्रण है–361, कर्नाटक चुनाव!–362, कर्नाटक का संदेश!–362, प्लासी युद्धः भारत की सबसे बड़ी हिस्ट्री चेंजर घटना!–363, मायावादियों के निशाने पर बहुजनों का प्रोफेसर नंबर वन!–364, भारत की गुलामी के लिए जिम्मेवारः ब्राह्मण और क्षत्रिय!–365, चुनावों पर आ गई मेरी एक और किताब!–365, राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता–367, नोवाक जोकोविच के फ्रेंच ओपन 2023 के सेमी फाइनल में पहुंचने से मिली मुझे भारी राहत!–367, मैंने मकबूल साहब को नंगे पांव चलते देखा था!–368, हरिशंकर परसाईः मेरे फेवरेट पत्रकारीय लेखक!–370, मिशन डाइवर्सिटी की एक और सफलता!–372, R Kumar के इस सवाल पर कि बहुजनवादी किसे माना जाय रूपेश है मेरा जवाब!–374, शाहू जी महाराज के जन्मदिन पर : क्या हो बहुजनों का संकल्प!–374, विपक्ष मुसलमानों के खिलाफ़ संचित बहुजनों की नफरत को नफरत को जन्मजात शोषकों की ओर शिफ्ट कराने की रणनीति पर काम करें!–379, आंबेडकरवाद के महान नायक एलआर बाली साहब को अशेष श्रद्धांजलि!–380, दुसाध का यूनिक ड्रेस सेंस!–383, इसरो की कहानीः विकिपीडिया की जुबानी!–385, तैयार हो गई है बहुजन मुक्ति की पर्फेक्ट परियोजना!–387, एक चमार की अद्भुत चुनौती!–392, अंतरिक्ष यात्रा में भी डाइवर्सिटी!–393, आरक्षण दिवस का सन्देश!–393, बहुजन आंदोलनों का एजेंडा लिलिपुट जैसा है!–395, दुसाध की नजरों में हिंदी पट्टी वालों के सुपर इंटेलेक्चुअल : नामवर सिंह!–396, मायावती जी के एक भक्त का उपदेश–398, यह पोस्ट नव बसपाइयों के लिए है!–399, मुझे कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए!–400, विराट के खिलाफ़ साजिश–401, दुसाध का दावा!–402, क्या दुसाध भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैंफलेटियर नहीं है!–404, स्वागत है आपका 17वें डायवर्सिटी डे उत्सव में!–404, सुअर चराने के अनुभव से समृद्ध दुसाध की 93% आबादी के दुश्मनों को चुनौती!–406, क्या आज की तारीख में साहेब कांशीराम : नागनाथ सांपनाथ का जुमला उछालते!–411, क्या टेनिस में कोको गॉफ के रूप में एक और सेरेना विलियम्स का उदय हो रहा है!–412, कोको गॉफ ने रच दिया इतिहासः बन गई महिला टेनिस की नई रानी!–413, स्पोर्ट्स में मेरे सबसे अच्छे 48 घंटे!–413, भारत के खिलाफ बाबर आजम का वनडे रिकॉर्ड क्या कहता है?–413, सभी जातियों के लोग पुजारी बनें : पेरियार–414, महिला आरक्षण बिल टेस्ट है सामाजिक न्याय की

राजनीति के नए आइकॉन का।—415, राहुल नहीं भूले हैं रायपुर का वादा!—416, कोटि कोटि नमन मैनेजर पांडे सर को!—417, यह बताने के लिए राहुल गांधी को अशेष धन्यवाद!—418, राहुल गांधी : बाबा या अब्बा!—419, Dilip C Mandal में उभरता : भाजपा प्रेम!—420, जितनी आबादी : उतना हक का भाजपा पर खौफ!—421, भारत के सर्वश्रेष्ठ पढ़ाकू : बालेन्दु शेखर!—421, क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा को ताबूत में कील ठोकना शुरू कर दिया!—423, दुसाध को यूं ही जानने वाले इनसाईक्लोपिडीया ऑफ क्रिकेट नहीं कहते—424, मैंने इसलिए अंग्रेजी की परवाह नहीं की—426, विमल मित्र के स्त्री पात्र—429, एशियाई और वेस्टर्न फास्ट बॉलर्स के बीच असल फर्क सुअर का मीट है!—431, मेरी देखी-सुनी 3 अफसोसनाक 90 जो शतक में कन्वर्ट न हो सकीं! 432, लार्ड मैकाले : एक अद्भुत फ़रिश्ता!—435, नए मिलेनियम के द्वार पर खड़े भारत की क्या रहीं 5 प्रधान समस्याएं!—435, दुसाध का चैलेन्ज!—437, बेहद खतरनाक खबर!—438, कोहली के बाद क्रिकेट के लॉ ऑफ एवरेज के शिकार : रोहित शर्मा!—439, लानत है बहुजन युवाओं पर—439, कोहली की मानसिक दृढ़ता—441, सावधान! कंफर्म हो गया कि मोबाइल हमारे मन की बातें समझने लगा है!—444, मैक्सवेल ने याद ताजी कर दी कपिल देव की!—445 क्योंकि मायावती जी भाजपा के अहसानों को आज भी नहीं भूली हैं!—446, भारत की सामाजिक-आर्थिक समस्या और आज की राजनीति—447, भारत का विक्टर ट्रम्पर : जीआर विश्वनाथ!—451, विशी प्रेम से जुड़े एक कमेंट पर मेरा जवाब!—452, भारत की सारी समस्याओं का समाधान दुसाध के पास है—454, क्रिकेट का विश्व कप मुकाबला और पनौती—455, हिंदुओं को पनौती मोदी कहने से इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए!—456, क्या संदेश दिया है 5 राज्यों का एक्जिट पोल!—460, हिन्दू ओपिनियन मेकर्स और दुसाध—460, भीषण आत्म मुग्ध दुसाध की एक और दाम्भिक घोषणा!—462, बीएसपी की भावना का जेनुइन प्रतिबिंबन!—463, मनुस्मृति-दहन दिवस का संकल्प!—464, बड़े दिन का बड़ा संदेश!—468, बड़े दिन पर विशेष गिफ्ट!—468

लेखकीय

मिशन डाइवर्सिटी : शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करवाने के मकसद से 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन'(बीडीएम) की ओर से प्रकाशित की जा रही पुस्तकों की एक नयी शृंखला है, जिसकी शुरुआत 2021 से हुई। इसी मकसद से बीडीएम की ओर से 2008 से 'आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं' शृंखला की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत अबतक 22 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से जो सबसे चुनौतीपूर्ण शृंखला शुरू हुई, वह 'डाइवर्सिटी इयर बुक' की रही, जिसकी शुरुआत 2006 हुई। इसमें भारत में चल रहे 'आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष' का सालाना इतिहास दर्ज होता रहा है। भारत के आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष का वार्षिक इतिहास रिकॉर्ड करते हुए 2021 तक मेरे संपादन में इयर बुक की औसतन 1000 पृष्ठों की 15 वार्षिकियां प्रकाशित हुई। किन्तु हजार से डेढ़ हजार पृष्ठों की डाइवर्सिटी इयर बुक निकालना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम रहा। इसमें बेहिसाब समय देने के साथ ही संगठन को भारी आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ता रहा। ऐसे में जब इयर बुक निकालने की चुनौती झेलना कठिन लगने लगा, तब डाइवर्सिटी मूव्हमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 'मिशन डाइवर्सिटी' निकालने का निकालने का निर्णय लिया गया। मिशन डाइवर्सिटीः 2023 इस सीरिज की चौथी किताब है, जिसमें बहुजन नजरिये से 2023 की महत्वपूर्ण आर्थिक-राजनीतिक घटनाओं के साथ फिल्म, मीडिया,स्पोर्ट्स, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अख़बारों से लेकर फेसबुक पर की गयी मेरी छोटी-बड़ी सभी टिप्पणियां संग्रहित हैं।

बहरहाल 2023 में भी मैंने अखबारों और पोर्टलों के लिए 50 से अधिक लेख, जबकि फेसबुक बुक के लिए डेढ़ सौ से अधिक पोस्ट लिखे। अखबारों से लेकर फेसबुक तक की मेरी टिप्पणियों में अन्यान्य वर्षों की भाँति काफी विविधता रही, लेकिन प्रमुखता आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं की रही। इस क्रम में फिल्मों पर 'बॉलीवुड को पुनर्जीवन दिया : पठान' (पृ. 55) तो खेलों पर 'माराडोना महानतम एक्टिविस्ट' जैसे लेख भी रहे (पृ. 70)। पुस्तक सप्लाई में लागू हो सामाजिक और लैंगिक विविधता (पृ. 87), ढूंढते रह जाओगे साहित्य अकादमी में डाइवर्सिटी (पृ.

92), इंटरव्यू बोर्ड में लागू हो सामाजिक और लैंगिक विविधता (पृ. 97) जैसे लेखों के जरिये विविधता प्रेमी पाठकों को सामग्री सुलभ कराया। आर्थिक विषमता की भयावहता से पाठकों को सावधान करने के लिए 'बेकाबू होती आर्थिक असमानता' (पृ. 28) तथा 'खुशहाली का एकमेव उपाय : शक्ति के स्रोतों में सामाजिक विषमता और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन' (पृ. 102) जैसे लेख लिखा। आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा कर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण लेख 'बाबा साहेब के सपनों के भारत निर्माण के लिए : विश्व इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी परियोजना' शीर्षक से लिखा (पृ. 35)। सामाजिक परिवर्तन की यह सबसे बड़ी परियोजना दरअसल एक हस्ताक्षर अभियान रही। इस हस्ताक्षर अभियान के जरिये आजादी की सौंवी वर्षगाँठ तक 50 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे की लड़ाई में जोड़ने की परिकल्पना की गई थी। 2023 की उस परिकल्पना को अब 'डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट' के बैनर तले कुछ ही माह में जमीन पर उतारने का काम शुरू होने जा रहा है।

2023 : भाजपा ने राममय बनाना चाहा : देश का माहौल

बहरहाल जहां तक राजनीति का सवाल है वर्ष 2023 लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए याद रखा जाएगा। काबिलेगौर है कि 2007 के बाद जब- जब लोकसभा के चुनाव अनुष्ठित हुए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से बड़ा आयोजन कर राजनीतिक दलों के समक्ष बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा अपनाने की अपील की जाती जारी रही। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 27 अगस्त, 2023 को 'डाइवर्सिटी डे' प्रोग्राम आयोजित कर संगठन की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के समक्ष एक अपील जारी की गई (पृ-210)। जहां तक लोकसभा चुनाव की तैयारियों का सवाल है 2023 में सत्ताधारी भाजपा की ओर से उसके परम्परागत तरीके आपनाए गए। चूंकि भाजपा की चुनावी सफलता में हेट पॉलिटिक्स का बड़ा योगदान रहा है इसलिए वह 2023 के शुरूआत से ही इसे तुंग पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रही, जिसका प्रतिबिम्बन 'शुरू हो गई : नफरत की राजनीति' (पृ-24), 'विपक्ष को ढूंढना होगा : भाजपा की नफरत की राजनीति का ठोस जवाब' (पृ-170) जैसे लेखों में हुआ है। 2023 में उसने एक और काम किया, वह यह कि उसने विदेशी विद्वानों के जरिये मतदाताओं पर यह मनोवैज्ञानिक हमला करवाया कि 2024 में भाजपा फिर जीतेगी। इस दिशा में उसके प्रयासों को 'सबसे आसान काम है भाजपा को शिकस्त देना' (पृ-107) और 'भाजपा की ताकत और कमजोरियां' (पृ-119) जैसे लेखों के जरिये सामने लाने का प्रयास किया है। जिस राम मंदिर आन्दोलन के सहारे भाजपा एक अंतराल के बाद अप्रतिरोध्य बन गई, उससे जुड़ी लोगों की आस्था को 2024 के लोकसभा चुनाव भुनाने के लिए

2023 के उत्तरार्द्ध में आरएसएस की ओर से देश का माहौल राममय बनाने की खुली घोषणा कर दी गई। उसके इस प्रयास से 'उद्धव ठाकरे की चुनौती' (पृ-225), 'सावधान राममय बनने जा रहा है देश का माहौल राममय' (पृ-229) जैसे लेखों के जरिए राष्ट्र को सावधान करने का प्रयास किया गया। बहरहाल भाजपा की लोकसभा चुनाव के तैयारियों को केन्द्रित करते हुए जितनी भी टिप्पणियां की, सबमें यही संदेश देने की कोशिश किया कि यदि विपक्ष चुनाव को सामाजिक न्याय पर केन्द्रित करने की कोशिश करे तो अप्रतिरोध्य होने के बावजूद भाजपा को हराना कोई कठिन काम नहीं होगा। सुखद आश्चर्य की बात यह रही कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उपलब्धि किया कि सामाजिक न्याय के जोर से ही भाजपा को मात दिया जा सकता है, इसलिए 2023 में उसने इस दिशा में ऐतिहासिक प्रयास किया, जिसकी शुरुआत उसने रायपुर अधिवेशन से की!

2023 की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटनाः कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन!

24 से 26 फरवरी, 2023 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 85 वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जहां से सामाजिक न्याय से जुड़े ऐसे-ऐसे प्रस्ताव पास हुए, जिसने देश- दुनिया के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया था। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ों यात्रा' के समापन के कुछ अंतराल बाद लोकसभा चुनाव 2024 की पृष्ठभूमि में रायपुर में अयोजित अपने 85वें अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार सामाजिक न्याय का पिटारा खोला था, जिसे देखकर राजनीति के पंडित हक्के- बक्के रह गये थे। इसी रायपुर अधिवेशन से कांग्रेस नें खुद में आमूल परिवर्तन करते हुए स्थाई तौर पर खुद को सामाजिक न्यायवादी दल के रूप में तब्दील करने का उद्योग लिया था। इसके तहत उसने यहां से सामाजिक न्याय से जुड़े जो प्रस्ताव पारित किए थे, उनमें से एक था उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रस्ताव। इस संबंध में कहा गया था,' यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका भारत की सामाजिक विविधता का प्रतिबिंब है, कांग्रेस पार्टी उच्च न्यायपालिका में एससी-एसटी-ओबीसी के लिए आरक्षण पर विचार करेगी। इसी भावना से भारतीय न्यायायिक सेवा आयोग बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे!' यहीं इन वर्गों के लिए आम बजट का हिस्सा निर्धारित करने और उनमें गरीब तबकों को ईडब्ल्यूएस कोटे मे शामिल करने का वादा किया गया था। रायपुर में ही महिला आरक्षण पर यू टर्न लेते हुए कोटे मे कोटे का समर्थन किया गया था। यह यू टर्न विस्मित करने वाला प्रस्ताव था क्योंकि 2010 में कांग्रेस ने यूपीए सरकार में कोटा के भीतर कोटा लाने के सहयोगी दलों की मांग को खारिज कर दिया था। रायपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने दशकीय जनगणना के साथ-साथ एक सामाजिक-आर्थिक जनगणना कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। जातिगत

जनगणना में गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों की भी जनगणना कराने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। रायपुर में ही एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले भेदभाव को दूर करने तथा उनके शिक्षा सम्मान के अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए 'रोहित वेमुला अधिनियम' बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। रायपुर से ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय विकास परिषद के तर्ज पर सामाजिक न्याय परिषद गठित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं एक बेहद अहम प्रस्ताव संगठन में दलित- बहुजनों को वाजिब भागीदारी देने से जुड़ा भी पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी ब्लॉक, जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर वर्किंग कमिटी में 50% स्थान दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए सुनिश्चित करेगी। इस किस्म के अन्य कई प्रस्ताव भी रायपुर अधिवेशन में पास हुए थे। देखें, ' कांग्रेस के इतिहास में पहली बार खुला : सामाजिक न्याय का पिटारा (पृ-78)!

रायपुर अधिवेशन : कांग्रेस के इतिहास में एक प्रस्थान बिन्दु

बहरहाल रायपुर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में एक प्रस्थान बिन्दु था, जहाँ से पार्टी ने सामाजिक न्याय की राह पर चलने की प्रतिबद्धता जाहिर करने के साथ ही खुद को एक सामाजिक न्यायवादी दल में तब्दील करने का संकेत किया था। तब वहां पारित सामाजिक न्याय से जुड़े प्रस्तावों को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने ही संदेह जाहिर करते हुए प्रायः एक स्वर में खुलकर कहा था कि जिस पार्टी के पण्डित नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे नेता काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें लागू करने से पीछे हट गये थे; जिस पार्टी के राजीव गांधी संसद में पानी पी-पी कर मंडल की सिफारिशों के खिलाफ घंटों बोले थे, क्या वह पार्टी रायपुर अधिवेशन में पारित सामाजिक न्याय से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकती है? लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक विश्लेषकों को भ्रांत करते हुए रायपुर से पारित प्रस्तावों पर इमानदारी से अमल करने का मन बनाया।

रायपुर अधिवेशन में पारित सामाजिक न्याय से जुड़े प्रस्तावों को आधार बनाकर कांग्रेस ने कर्णाटक चुनाव को सामाजिक न्याय पर केन्द्रित किया और भाजपा को ऐतिहासिक शिकस्त दे दी। कर्णाटक चुनाव में राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन के रूप में उभरे। परवर्तीकाल में रायपुर से पारित प्रस्तावों की फसल कर्णाटक के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में भी काटने का मन बनाया। रायपुर अधिवेशन का इम्पैक्ट 'मुस्लिम आरक्षण के खात्मे की ताक में : भाजपा' (पृ-143), 'कर्णाटक का संदेश : सामाजिक न्याय पर केन्द्रित हो 2024 का लोकसभा चुनाव' (पृ-150) जैसे लेखों में देखा जा सकता है! रायपुर से पारित प्रस्तावों के कर्णाटक में प्रयोग के बाद राहुल गांधी में यह विश्वास पनपा कि 'सामाजिक न्यायवादी विजन

ही भाजपा को हरा सकता है' (पृ. 165)। फिर क्या था अक्तूबर आते-आते कांग्रेस ने लोकसभा 2024 के लिए अपना एजेंडा स्थिर कर लिया। पढ़ें, 'तो कांग्रेस ने तय कर लिया लोकसभा का चुनावी एजेंडा' (पृ. 254)। लोकसभा चुनाव 2024 की पृष्ठभूमि में रायपुर से जो प्रस्ताव पारित हुए थे उसे धीरे-धीरे नहीं, बड़ी तेजी से 2024 के लोकसभा चुनाव का अपना एजेंडा बनाते हुए कांग्रेस ने 5 अप्रैल, 2024 को 25 गारंटी और 300 वादों से युक्त 'न्याय पत्र' नाम से अपना घोषणापत्र निकाला, जिसे तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने एक स्वर में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया। उस घोषणापत्र पर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने जो राय दी थी, वह उम्मीद से कहीं आगे निकल गया। जो लोग यह मानकर चल रहे थे कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जायेगा, ऐसे लोगों की धारणा में कांग्रेस के घोषणापत्र ने रातों-रात बदलाव ला दिया था, जिसके फलस्वरूप मोदी जैसे-तैसे अपनी हार बचा पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिदृश्य बदलने वाला कांग्रेस का न्यायपत्र मूलतः रायपुर प्रस्ताव का ही विस्तार था!

जाति जनगणना के लिए संघर्ष

रायपुर से निकले प्रस्तावों ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव पर असर डाला, बल्कि कांग्रेस में तो आंतरिक क्रांति ही घटित कर दिया, जिसके फलस्वरूप कल की सवर्णवादी कांग्रेस की शक्त अब काफी हद तक बहुजनवादी होती जा रही है। रायपुर से निकले प्रस्तावों का ताजा असर जातीय जनगणना पर भी पड़ा है। 30 अप्रैल, 2025 को मोदी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई कि सारकार जातिवार जनगणना कराएगी। यह एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ऐसी जनगणना आखिरी बार 1931 में ब्रितानी सरकार ने कराई थी। उसने 1881 से 1931 जातीय जनगणना कराई। 1941 में भी जातीय आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। उस समय सरकार ने तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आंकडे ही जुटाए जायेंगे। सरकार का मानना था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। जाति जनगणना से केंद्र सरकारों के पीछे हटने के बावजूद इसकी समय-समय पर मांग उठती रही जो 2009 से जनहित अभियान, बामसेफ, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन सहित दलित बहुजनों के ढेरों संगठनों और बुद्धिजीवियों की सक्रियता तथा लालू-मुलायम शरद यादव की तिकड़ी के प्रयास से काफी तेज हो गई। इनके दबाव में मनमोहन सिंह सरकार 2011 में सर्वेक्षणों की शक्ल में सामाजिक-आर्थिक जनगणना कराया, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद भी जाति जनगणना की मांग जारी रही। इसमें नया मोड़ तब आया, रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन से सामाजिक न्याय से जुड़े हैरतंगेज प्रस्ताव पारित हुए।

खैर! अगर 1931 के प्रायः 95 वर्ष अंतराल के बाद जो जाति जनगणना होने जा रही है तो उसके तार रायपुर अधिवेशन से ही जुड़े हुए हैं!

जितनी आबादी-उतना हक के लिए चाहिएः जाति जनगणना

रायपुर अधिवेशन में सामाजिक न्याय से जुड़े जो ढेरों प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें जाति जनगणना से जुड़ा एक खास प्रस्ताव भी था, जिसमें कांग्रेस की ओर से जातिवार जनगणना के साथ-साथ एक सामाजिक-आर्थिक जनगणना कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। जातिगत जनगणना में गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों की भी जनगणना कराने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। रायपुर अधिवेशन में जाति जनगणना का प्रस्ताव पास होने के बाद राहुल गांधी लगातार इसकी हिमायत करते रहे पर, ज्यादा मुखर हुए नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद। पिछले प्रायः तीन दशकों से लंबित पड़ा महिला आरक्षण विधेयक जब सितम्बर 2023 के तीसरे सप्ताह में 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' के रूप में पास हुआ, उस पर राय देते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले तो 2010 में राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे का प्रावधान न किये जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से माफ़ी माँगी। उसके बाद उच्च पदों पर ओबीसी, दलित, आदिवासियों सचिवों की निहायत ही कम उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा था,' भाजपा दो मुद्दों : अडाणी और जातीय जनगणना से डरती है। हमारी सरकार बनते ही हम जातीय जनगणना कराएँगे ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासियों का आंकड़ा जानकार उस हिसाब से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जातीय जनगणना इस तस्वीर को साफ़ करेगी कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की संख्या कितनी है और इसी आधार पर उन्हें देश चलाने में भागीदारी मिलेगी।' नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के दो सप्ताह के अन्दर जब 2 अक्तूबर को बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, राहुल गांधी इसके पक्ष में और मुखर होते हुए कहे,' बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84 प्रतिशत हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन ओबीसी है। इसलिए भारत के जातिगत आंकडें जानना जरुरी हैः जितनी आबादी-उतना हक़ हमारा प्रण है।' उसके बाद तो वह लगातार इसकी मांग उठाते रहे। देखें,' सामाजिक न्याय का परमाणु बम : जितनी आबादी उतना हक़' (पृ-230)।

जाति जनगणना का असर

फरवरी, 2023 के रायपुर अधिवेशन के बाद से राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने जाति जनगणना की जो मांग उठाना शुरू किया, 14 जनवरी, 2024 से शुरू हुई 'भारत जोड़ों न्याय यात्रा' में वह तुंग पर पहुंच गई। इस यात्रा में वह जगह-जगह

कहते रहे—'देश की 500 कंपनियों की लिस्ट निकाल लीजिये और ढूंढिए कि उनमें कितनों के मालिक और मैनेजर दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं? कितने प्राइवेट हास्पिटल, यूनिवर्सिटीज, अखबारों और टीवी चैनलों के मालिक दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं? हमारा उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक : दोनों तरह के न्याय सुनिश्चित कराना है। सामाजिक न्याय के लिए हम जाति जनगणना का आह्वान करते हैं, जो समाज में एक्सरे की तरह है। एक बार ऐसा हो गया तो हम एमआरआई के लिए जा सकते हैं।' उनकी इस मांग के समर्थन में सपा, राजद इत्यादि इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी साथ आए। इससे चुनाव सामाजिक न्याय पर केन्द्रित हो गया और 400 पार का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी केचुआ और अपने तंत्र के सहारे जैसे-तैसे हार बचाने में समर्थ हुए। लोकसभा चुनाव बाद भी राहुल गांधी एक पल के लिए भी जाति जनगणना से ध्यान नहीं हटाए। वह संविधान सम्मेलनों के जरिये जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे। और संसद के शीतकालीन सत्र में खुली घोषणा कर दिए कि हम इसी लोकसभा में सरकार से जातीय जनगणना करवाकर मानेंगे! तब उनकी मांग और भाषणों को भाजपा और सरकार ने हवा में उड़ा दिया था, लेकिन आज जब अचानक केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाने की घोषणा कर दी है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। भाजपा और उसकी समर्थक मीडिया इसे मोदी का मास्टरस्ट्रोक बताते हुए यह संदेश देने की मुहीम छेड़ी हुई है कि मोदी ने राहुल गांधी का मुद्दा हाईजैक कर लिया है। क्या यह सच है कि मोदी ने राहुल गांधी का मुद्दा हाईजैक कर लिया है? ऐसा बिलकुल नहीं है! इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जनगणना को देश को विभाजित करने वाला प्रयास बताते रहने वाले मोदी ने नोटबंदी, तीन तलाक, कृषि कानून वापसी इत्यादि सहित अन्य जितनी भी बड़ी घोषणाएं किया, मन की बात में सगर्व उस पर रौशनी डाला है : एक मात्र अपवाद है जाति जनगणना,जिस पर न तो उन्होंने ही कुछ कहा है और न ही उनके चाणक्य अमित शाह ने! यह इस बात का संकेतक है उन्होंने इसकी घोषणा विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के दबाव में की है!

बहरहाल जातीय जनगणना पर श्रेय लेने की होड़ के मध्य राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते थे कि देश में सिर्फ चार जातियां हैं, लेकिन अचानक उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। हम देश में जातिगत जनगणना के माध्यम से एक नए तरीके का विकास लाना चाहते हैं। चाहे ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी, इनकी देश में कितनी भागीदारी है, यह सिर्फ जातिगत से पता चलेगा, लेकिन हमें और आगे जाना है। हमें पता लगाना है कि देश की संस्थाओं और पॉवर स्ट्रक्चर में इन लोगों की कितनी भागीदारी है। इसके अलावा, कांग्रेस

पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आर्टिकल 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाय और हमारी मांग है कि सरकार इसे तत्काल लागू करे! मैं उन लाखों लोगों और संगठनों को बधाई देता हूँ, जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। बहरहाल मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने की तो घोषणा कर दी है पर, सवाल पैदा होता है क्या यह पॉवर स्ट्रक्चर और संपदा-संस्थाओं से बहिष्कृत दलित, आदिवासी, पिछड़े और आधी आबादी को उसका प्रप्य दिलाने में कामयाब हो पायेगी?

कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा संघ-भाजपा की हिन्दू धर्मशास्त्रों में गहरी आस्था से

इस सवाल का जवाब ढूँढने के पहले यह बुनियादी तथ्य विस्मृत नहीं करना होगा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाओं की शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार के मूल है शासन-प्रशासन पर काबिज वर्गों में क्रियाशील हिन्दू धर्म के प्रति गहरी आस्था। संविधान के जनक बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने राष्ट्र को संविधान सौंपने के एक दिन पूर्व : 25 नवम्बर,1949 को राष्ट्र को सावधान करते हुए कहा था कि हमें निकटतम भविष्य के मध्य आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा कर लेना होगा, नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता लोकतंत्र के उस ढाँचे को विस्फोटित कर सकती है, जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। लेकिन लोकतंत्र के विस्फोटित होने की संभावना के बावजूद शासन-प्रशासन पर कबिज लोगों ने विषमता के खात्मे की दिशा में आन्तरिक प्रयास नहीं किया और आज आर्थिक और सामाजिक विषमता के मामले में भारत प्रायः विश्व चैम्पियन बन चुका है। उन्होंने यह प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ों और आधी अबादी को शक्ति के स्रोतों- आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक,धार्मिक - में वाजिब हिस्सेदारी देनी पड़ती और ऐसा करना धर्म विरुद्ध होता, क्योंकि इनका शक्ति के स्रोतों का भोग हिन्दू धर्म में अधर्म घोषित है : शक्ति के स्रोतों के भोग का एकमात्र अधिकारी वर्ग हिन्दू- ईश्वर के उत्तमांग (मुख, बाहु, जंघे) से जन्मे लोग हैं। हिन्दू धर्म में शक्ति के समस्त स्रोतों के भोग का अधिकार सिर्फ उच्च वर्णों को है, इसलिए आजाद भारत के शासक संस्थाओं और पॉवर स्ट्रक्चर इत्यदि में दलित बहुजनों और महिलाओं को हिस्सेदारी देने में स्वतःस्फूर्त रूप से आगे नहीं बढ़े। चूँकि हिन्दू धर्म के ठेकेदार बनी भाजपा के लोगों में हिन्दू धर्म के प्रति आस्था अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा गहरी रही,इसलिए वे हिन्दू धर्म के रक्षार्थ शक्ति के स्रोतों में दलित बहुजनों की भागीदारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर रहे! चूँकि आरक्षण से दलित-बहुजनों को शक्ति के उन स्रोतों के भोग का अधिकार मिल जाता है, जिसके दैविक अधिकारी सिर्फ तीन उच्च वर्ण के लोग रहे, इसलिए भाजपा का पितृ संगठन पूना पैक्ट के ज़माने से आरक्षण

का विरोधी रहा। और 7 अगस्त, 1990 को जब मंडल रिपोर्ट के जरिये आरक्षण के विस्तार का अवसर मिला, भाजपा ने राम जन्मभूमि मुक्ति के नाम पर आजाद भारत में सबसे बड़ी प्रतिक्रांति कर दी। आज भी वह गुलामी के प्रतीकों की मुक्ति के नाम पर लगातार हिन्दुओं को ध्रुवीकृत करने की मुहीम में जुटी हुई है तो उसका अभीष्ट हिन्दू धर्म की रक्षा ही है, जो आरक्षण से क्षतिग्रस्त होता है। आरक्षण से हिन्दू धर्म को बचाने के लिए ही भाजपा के मोदी ने राममंदिर के सहारे मिली राजसत्ता का इस्तेमाल उन संस्थानों को बेचने में किया जहाँ दलित बहुजनों को आरक्षण मिलता है। मोदी राज में लागू ईडब्लूएस आरक्षण, लैटरल इंट्री इत्यादि का लक्ष्य हिन्दू धर्म की रक्षा ही है! हिन्दू धर्म की रक्षा के कारण महिला आरक्षण बिल पूरी तरह बेअसर हो गया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से सबक ले : कांग्रेस

राहुल गांधी तथा अखिलेश और तेजस्वी यादव जैसे लोग अगर सोचते हैं कि जाति जनगणना से संस्थानों और पॉवर स्ट्रक्चर में दलित, आदिवासी, पिछड़े व अन्य वंचित की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा तो महिला आरक्षण विधेयक के नए रूप : 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम से सबक ले सकते हैं। पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा महिला आरक्षण विधेयक नरेंद्र मोदी ने विपुल संख्या बल के सहारे सितम्बर, 2023 में बदले नाम : नारी शक्ति वंदन विधेयक को बड़ी आसानी से पारित करा लिया। महिला आरक्षण में कोटा में कोटा हो, इसकी लड़ाई सामाजिक न्यायवादी दल वर्षों से लड़ रहे थे। किन्तु मोदी ने संसद में जबरदस्त संख्या बल के सहारे इसे इस रूप में पास करा लिया कि जिन तबकों द्वारा शक्ति के स्रोतों के भोग से हिन्दू धर्म क्षतिग्रस्त होता है, उन तबकों की महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कुछ मिला ही नहीं। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए इस पुस्तक के दो लेख : 'नारी शक्ति वंदन विधेयक मोदी सरकार के ताबूत में एक कील साबित होने जा रहा है' (पृ-233) और 'मैंने क्यों नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दहन किया' (238) पढ़ने का विशेष अनुरोध करूँगा। भाजपा और संघ की हिन्दू धर्म में गहरी आस्था शर्तिया तौर पर मोदी को जाति जनगणना के खिलाफ और निर्मम रुख अख्तियार करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि इससे जो आरक्षण अब तक मुख्यतः सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तक महदूद था, वह निजी क्षेत्र से लगाए समस्त पॉवर स्ट्रक्चर तक प्रसारित होकर सर्वव्यापी आरक्षण का रूप अख्तियार कर लेगा, जो हिंदुत्ववादियों के सहन सीमा के बाहर हो जायेगा। ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि ब्लॉक से लेकर जिले स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जिन वर्गों को पॉवर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, उन वर्गों तक संदेश पहुंचाएं कि जाति जनगणना के बाद कांग्रेस क्या करना चाहती है। इसके जरिये यदि वंचितों में पॉवर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी की उग्र चाह

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

• Curate diverse book collections

• Support authors from marginalized communities

• Provide free resources to educators

• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library